

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।
(विधि शाखा)

अधिहरण (Confiscation) वाद सं०-115/2023-24

सरकार

-बनाम-

अभिषेक कुमार वगै०

आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक -2973/अप०शा० दिनांक -07.11.2023 के द्वारा वादी श्री रविन्द्र कुमार पांडेय पे०-भागीरथ पांडेय, वर्तमान अंचल अधिकारी बसिया जिला-गुमला के लिखित आवेदन के आधार पर बसिया थाना काण्ड सं०-76/2023 दिनांक-07.10.2023 धारा-379/411 भा०द०वि०, 54 झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली-2004 एवं 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भण्डारण) नियम-2017 एवं 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियम) अधिनियम-1957, के तहत अवैध रूप से बालू का उत्खनन एवं परिवहन करने के आरोप में जप्त हाईवा रजि० सं० - JH02BH-3040 के मालिक अभिषेक कुमार पे०- दिलीप कुमार सा०- थाना रोड सिसई, थाना - सिसई, जिला-गुमला एवं हाईवा रजि० सं० - JH01DB-7953 के मालिक गुप्तेश्वर कुमार सिंह, पे० - विजय कुमार सिंह सा०- गुरुगाई, थाना - बुडमू जिला- रौंछी के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन में अंकित है कि जिला खनन पदाधिकारी गुमला के कम्प्यूटरकृत आवेदन के आधार पर प्राथमिक अभियुक्त हाईवा रजि० सं० - JH02BH-3040 के मालिक अभिषेक कुमार पे०- दिलीप कुमार सा०- थाना रोड सिसई, थाना - सिसई, जिला-गुमला एवं हाईवा रजि० सं० - JH01DB-7953 के मालिक गुप्तेश्वर कुमार सिंह, पे० - विजय कुमार सिंह सा०- गुरुगाई, थाना - बुडमू जिला- रौंछी के विरुद्ध अवैध रूप से बालू का उत्खनन कर परिवहन करने करने के आरोप में अंकित किया गया है एवं इस कांड के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 (यथा) संशोधित) के नियम-4 एवं 54 MMDR Act. 1957 के धारा-4 एवं 21 तथा Jharkhand Minerals Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rules-2017 के नियम-7 एवं 13 के तहत मालिक के विरुद्ध सत्य पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक गुमला से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, नोटिस तामिला के बाद भी विपक्षीगण लगातार अनुपस्थित रहें। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी को कुछ नहीं कहना है। पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जप्त हाईवा रजि० सं० - JH02BH-3040 एवं हाईवा रजि० सं० - JH01DB-7953 के द्वारा बालू का उत्खनन कर परिवहन करने के आरोप को सत्य पाया गया है।

The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) 2017 के Rule 7 में यह अंकित है कि:-

(1) "No person other than a dealer or a mining lease holder shall buy or store or sell or offer for sale or engage in any transaction of buying, selling, processing

any mineral at any place or transport mineral for commercial gain without being registered as a dealer."

(2) Rule 11 (V) के अनुसार Any minerals tool equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court.

(3) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi के मूल आवेदन सं०-360/2015 प्रतिवेदित तिथि 15.01.2021 में यह अभिकथन किया गया है कि "Another issue bearing on the enforcement mechanism is the action against the vehicles used in illegal sand mining. Seizure of such vehicles is required and release of seized vehicles lightly defeats the purpose of the coercive measures. Since the vehicles are in a way weapon of offence, the same cannot be dealt with in the manner disputed property is dealt with under section 451 Cr.PC. by releasing the same in favour of the ostensible owner by taking an entrustment /indemnity bond/sapurdginama. In Sujit Kumar Rana"

अंकनीय है कि इस तरह के मामलों में उपयोग किये जाने वाले वाहन में पंजीकरण संख्या नहीं रहती है, तथा वाहनों से संबंधित वैध कागजात नहीं होने के कारण उसको अवैध रूप से परिवहन कार्य कराया जाता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त बालू एवं वाहन का परिवहन माईनिंग प्रावधानों के विरुद्ध किया गया है। उक्त वाहन एवं बालू के संबंध में claim (दावा) नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त तथा N.G.T. न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय के आलोक में उक्त जप्त बालू एवं जप्त हाईवा रजि० सं० - JH02BH-3040 एवं हाईवा रजि० सं० - JH01DB-7953 को राजसात करता हूँ।

आदेश के प्रति सभी संबंधित अधिकारी को दे।

लेखापित एवं संशोधित


उपायुक्त,
गुमला


उपायुक्त,
गुमला